EDITORIAL

Merger of MTNL

The issue of Merger of MTNL with BSNL is again in the corridors of decision makers, the GOI. In today's situation it is unpatriotic to speak against Govt. if they say adding minus with minus is plus, even it goes against common sense and school mathematics. The issue of MTNL merger is one such case.

The Merger and Acquisition policy (M&A policy) of the Govt. is enabling the companies to act accordingly. NFTE has forewarned when the policy was announced. The private telcos will do mergers or establish subsidiary units as per their profit and capital base wisdom and to lessen their tax to GOI. It is not difficult to understand their game plan of doing business with all unfair trade practices. But the business model of PSUs is different and has its own social and economical ethics. Unfortunately the PSUs are being pressurized to copy the model of Private Board Room decisions. In the merger of MTNL one should not copy the model of Voda-Idea type or Reliance- Aircel vertical merger like Wireless networks.

Thirty years back, it was claimed formation of separate Metro Corporation like MTNL was the growth model. Today it gets stagnated, loss making and its Networth is also eroded. Now their wisdom is dictating merger of loss making units to make them viable. In a democracy, Govt. has right to take any decision and in the same way the stake holders like us are also having right to protest and enrich the decision to bring some win-win situation.

Two years back, we were told that DOT had set-up some internal committee to study about financial, technical and HR issues of the Merger. They are trying to solve the issue of technical compatibility. The Revised Companies act of 2013 is helping them to merge the listed company with the unlisted one. The issue of pension by GOI is almost settled for the MTNL pensioners but they are some more issues like Leave Rules, Promotional aspects, Medical and specially the issue of parity of pay scales for Non-Executives.

The prime issue is absence of transparency. When SEBI (Stock Exchange Board of India) has sought compliance about the news item about merger, the MTNL company secretary has replied to SEBI on March 8th 2017 that we were not aware of any such news. As per the report of Economic Times dt. March 19th CMD BSNL is reporting the merger move will be advantageous and augur well. These kind of varied voices disturb the employees.

There are many questions that need transparent clarifications for wide discussion of the issue.

a. Whether MTNL is going to be acquired by BSNL and made to function as two metro units like Chennai and Kolkata or the merger is like Air India and Indian Airlines?
b. What is the guarantee for the resultant entity, as Govt. has decided 'NO Budgetary Support'?
c.. Whether Govt. is going to plough back (getting back the shares of listed MTNL) the shares?
d. There is a policy of Govt. that excess spectrum will be levied as per market price- what will happen if it is levied? Will it not affect BSNL financial viability?
e. There are reports about excess manpower in BSNL. If MTNL's additional 40000 is added what is the guarantee for Job security? Will it affect the coming wage revision?
f. What is the remedial action for pay parity before the new wage revision?
g. What will happen to the status of Navaratna? Whether the merged entity will get that navaratna/ maharatna status?

The M&A policy is telling that many aspects need to be considered to ensure if a proposed company is right or not for a successful merger. Unions cannot be limited with HR boundaries as the other financial and corporate integration is also important. NFTE strongly feel that the relevant questions raised by Unions and associations need clarifications beyond any ambiguity. Let us hope that the DOT and BSNL would take the Unions into confidence and add necessary inputs in the cabinet note before the same get its nod from Govt. to avoid industrial unrest.

संपादकीय

महानगर टेलीफोन निगम का विलयन

महानगर टेलीफोन निगम लि. (एन.टी.एन.एल.) का भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) के साथ बिलयन भारत सरकार के नीति निर्णायक मंडल के दहलीज पर है। आज के परिस्थिति में भारत सरकार के संबंध में कुछ भी कहना देश भक्तिहीनता है, अगर वे कहते हैं कि दो ऋणात्मक का योग धनात्मक होगा हालांकि यह आरम्भिक गणित एवं आम सोच के विरूद्ध है। एम.टी.एन.एल. का विलय भी एक ऐसा ही मुद्दा है।

भारत सरकार की विलयन एवं अधिग्रहण नीति कम्पनियों के लिए असंगत है। इस नीति के उद्घोषणा के समय ही एन.एफ.टी.ई ने चेतावनी दी थी। निजी कम्पनियां अपने आर्थिक लाभ एवं पूंजी अधारित चलाकी से सरकारी कर को कम करने के लिए आपसी विलयन अथवा सहायक कम्पनियों की स्थापना करती हैं परन्तु लोक उपक्रमों की आदर्श व्यापारिक नीति इससे भिन्न हैं और इनकी अपनी सामाजिक एवं आर्थिक अचारसंहिता हैं। दुर्भाग्यवश लोकउपक्रमों को निजी कम्पनियों के अन्तः निर्णय को अपनाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। एम.टी.एन.एल. एवं बी.एस.एन.एल. के विलयन को वोडाफोन आइडिया या रिलायन्स – एयरसेल के विलय की तरह नहीं देखा जाना चाहिए।

तीस साल पूर्व एम.टी.एन.एल. के स्थापना को दूरसंचार की विकास यात्रा का नमूना बताया गया था। आज यह अवरूद्ध होकर घाटे पर चलने वाली और सकलपूंजी हासित हो गई है। आज उनकी बुद्धि को हानिप्रद उपक्रमों का विलय करके उनको आर्थिक जीवंतता देने की बात समझाती है। लोकतंत्र में सरकार फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है साथ ही हम सैद्धांतिक हिस्सेदारों को भी प्रतिरोध करने तथा फैसले को बदलावा कर सापेक्ष सुशोभित स्थिति लाने का अधिकार है।

दो वर्ष पूर्व हमें बताया गया था कि दूरसंचार विभाग ने बिलयन के लिए आन्तरिक कमिटी गठित कर आर्थिक, तकनिकी एवं मानवसंसाधन (कार्मिक) विषयों का अध्ययन करा रही है। सन् 2013 की परिवर्तित कम्पनी अधिनियम सूचीबद्ध कम्पनी को गैर सूचीबद्ध कम्पनी के साथ विलयन का रास्ता खोलती है। एमटीएनएल के पेंशनरों के लिए सरकार ने समाधान निकाल दिया है परन्तु अभी भी अनेकों मुद्दों जैसे अवकाश, चिकित्सा, पदोन्नति एवं विशेष नान–एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों के वेतन में समानता आदि लम्बित है।

पारदर्शिता का अभाव है। जब स्टॉक इक्सचेंज ऑफ इन्डिया ने एमटीएनएल से विलयन पर हो रहे चर्चा की जानकारी मांगी तो दिनांक 8 मार्च 2017 को एमटीएनएल के कम्पनी सेक्रेट्री ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा की ऐसी कोई सूचना कम्पनी को नहीं है और 19 मार्च 2017 के इकोनामिक टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक सी.एम.डी. (बीएसएनएल) ने कहा है कि दोनों कम्पनियों का बिलयन लाभदायक एवं भविष्य बदलने में सहायक होगा। इस तरह के विभिन्न बयान कर्मचरियों को भ्रमित करते हैं। विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए बहुत से सवालों का पारदर्शी स्पष्टीकरण आवश्यक है।

1. क्या एमटीएनएल को बीएसएनएल अधिग्रहित करेगा और इसके दो इकाई दिल्ली और मुम्बई, बीएसएनएल के दो मेट्रो यूनिट चेन्नई तथा कोलकता की तरह काम करेगा।

2. जब सरकार कोई बजटीय रिपोर्ट नहीं देगी तो भावी विलयित कम्पनी की क्या भविष्य होगी।

3. क्या सरकार एमटीएनएल के विनिवेशिक हिस्से पूंजी को वापस लायगी।

4. सरकार के नीतियों के अनुरूप अधिक स्पेक्ट्रम के लिए अलग से शुल्क देय होगा क्या इससे बीएसएनएल की आर्थिक स्थिति प्रभावित नहीं होगी?

5. कहा जाता है कि बीएसएनएल में कर्मचारियों की संख्या अधिक है क्या एमटीएनएल के लगभग चालीस हजार कर्मचारियों के जुड़ने से सेवा के गारन्टी एवं वेतन पुनरीक्षण पर क्या प्रभाव होगा।

6. विलय से पूर्व वेतन समानता के लिए कौन सा कदम

उठाये जा रहे हैं।

7. नवरत्ना स्टैटस का क्या होगा क्या विलय के बाद यह स्तर मिलेगा। विलयन एवं अधिग्रहण नीति में बहुत से संभावित जरूरतें हैं जिन पर विचार कर यह सुनिश्चित करना होगा कि कम्पनियों का विलयन उचित अथवा अनुचित है। यूनियन केवल मानव संसाधन के सवालों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि आर्थिक एवं निगमित पहलू भी महत्वपूर्ण है। एनएफटीई की यह स्पष्ट धारण है कि यूनियन/एशोसियेशन द्वारा उठाये गये सवालों का स्पष्ट एवं पारदर्शी स्पष्टीकरण होनी चाहिए। हमें आशा है कि दूरसंचार विभाग एवं बीएसएनएल कर्मियों को विश्वास में लेकर और आवश्यक बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मंत्री परिषद के लिए नोट तैयार करेगी ताकि औद्योगिक शान्ति स्थापित रह सके।